2 राजस्व प्रकरणों पर दें विशेष ध्यान-रजनी सिंह

5 उत्तराखंड की राजनीति का एक सशक्त अध्याय

6 देश में नशे के विरुद्ध निर्णायक युद्ध

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 10 प्रति सोमवार, 20 जुलाई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

सरदार सरोवर बांध: मध्यप्रदेश को 7,769 करोड़ मिलने की जगह 550 करोड़ चुकाने की नौबत?

अपने हितों की आहूति देकर नतमस्तक हो गई मप्र सरकार

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

सरदार सरोवर बांध को लेकर हुई हालिया बैठक के बाद मध्यप्रदेश के हितों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश को परियोजना से जुड़े वित्तीय समायोजन में गुजरात से लगभग 7,769 करोड़ रुपये प्राप्त होने चाहिए थे, उसी मध्यप्रदेश पर अब करीब 550 करोड़ रुपये के भुगतान का दायित्व आ गया है। यह राज्य के लिए बड़ा वित्तीय झटका है। सबसे अधिक डूब क्षेत्र और विस्थापन मध्यप्रदेश में होने के बावजूद राज्य ने अपने हितों से समझौता किया। यहां मप्र सरकार ने अपने हितों को दरकिनार करते हुए बैठक में नतमस्तक हो गई। और 7,769 करोड़ का नुकसान करवा लिया। जाहिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा की गुजराज लॉबी के दवाब में आकर इस तरह समझौता करके मध्यप्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। यह विवाद 30 वर्षों से चल रहा था और गुजरात पर मध्यप्रदेश की अदायगी थी लेकिन गुजरात शुरू से ही पैसे देने में आनाकानी करता आ रहा था।

सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजनाओं में से एक है, जिसमें जल, बिजली और लागत का बंटवारा संबंधित राज्यों के बीच तय नियमों के अनुसार किया जाता। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। (शेष पेज 2 पर)

नीली क्रांति से समृद्धि की ओर: मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आधार

-विजया पाठक

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती देश के समग्र विकास की आधारशिला मानी जाती है। बदलते समय के साथ यह महसूस किया गया कि केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहकर किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। यही कारण है कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे सहायक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें मछली पालन आज सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है। यह न केवल पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का माध्यम है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी साधन भी बन चुका है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए "नीली क्रांति" ने देश के मत्स्य क्षेत्र को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। छत्तीसगढ़ जैसे जल संसाधनों से समृद्ध राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। यहाँ बड़ी संख्या में तालाब, जलाशय, नदियाँ और सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिनका उपयोग मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन को संगठित स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

आर्थिक जोखिम भी कम हो जाता है

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार किसानों से यह आग्रह कर रहे हैं कि वे अपनी खेती को केवल धान उत्पादन तक सीमित न रखें। वे दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाकर अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाएँ।

(शेष पेज 2 पर)

भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 40 वर्षों से हो रहा लोहा चोरी

पहले पिता दलवीर सिंह, अब बेटा इन्द्रजीत कर रहा लोहा चोरी

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 40 वर्षों से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोहे की चोरी होने का दावा किया गया है। इस मामले ने तब बड़ा रूप ले लिया जब दुर्ग पुलिस ने भिलाई में बड़े पैमाने पर हो रहे एक संगठित लोहा चोरी रैकेट (सिंडिकेट) का पर्दाफाश किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित स्टील प्लांट से कबाड़ी से बना एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर पिछले 40 वर्षों से लोहा चोरी का काम कर रहा है। (शेष पेज 3 पर)

लोकतंत्र की मर्यादाओं को भूले आज के युवा नेता

संसदीय मर्यादा के शिखर पुरुष रहे हैं कमलनाथ

-विजया पाठक

लोकतंत्र केवल बहुमत का खेल नहीं है, बल्कि यह संवाद, सहमति और सबसे बढ़कर 'मर्यादा' का नाम है। कमलनाथ का पूरा जीवन इसी मर्यादा को स्थापित करने और उसे जीने का एक जीवंत दस्तावेज रहा है। चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम जिम्मेदारियाँ हों, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद हो या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका। उन्होंने हर दायित्व को जिस शिष्टता और गंभीरता से निभाया, वह आज की पीढ़ी के लिए एक महान सीख है। एक दौर था जब संसद और विधानसभाओं में पक्ष और विपक्ष के बीच केवल तीखी बहसें नहीं होती थीं, बल्कि वैचारिक मंथन होता था। विषय विशेषज्ञ अपनी बात पूरी गहराई से रखते थे। (शेष पेज 3 पर)

राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर दें विशेष ध्यान- कलेक्टर रजनी सिंह

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आरसीएमएस की प्रगति, एसडीएम एवं तहसील स्तर पर लंबित राजस्व प्रकरणों, पीठासीन अधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों तथा गिरदावरी और फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों, अभिलेख दुरुस्ती, नजूल पट्टों के नवीनीकरण, भूमि आवंटन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुशासन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जनसुनवाई, 100 दिवस की सीएम हेल्पलाइन, अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों, सीएम हाउस, कार्यालय एवं आयोगों से प्राप्त शिकायतों तथा सीपी ग्राम पोर्टल पर लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में धारणाधिकार के लंबित प्रकरणों, राजस्व वसूली, आरबीसी 6(4) के प्रकरण, हिट एंड रन, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के लंबित मामलों तथा किसान कल्याण से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई।

सरदार सरोवर बांध; मध्यप्रदेश को 7,769 करोड़ मिलने की जगह 550 करोड़ चुकाने की नौबत?

(पेज 1 का शेष)

यह केवल वित्तीय मामला नहीं बल्कि राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक हितों से जुड़ा विषय है। इस निर्णय का असर करोड़ों लोगों और राज्य की विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखे जाने के आरोप लग रहे हैं। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का उद्देश्य गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच जल एवं बिजली का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना था। लेकिन समय-समय पर जल प्रबंधन और बांध के संचालन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। मध्यप्रदेश नर्मदा बेसिन का सबसे बड़ा भागीदार होने के बावजूद अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। यह परियोजना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका, कृषि और जल सुरक्षा से जुड़ा विषय है। बैठक में वास्तव में मध्यप्रदेश की प्रमुख मांगों की अनदेखी हुई है, इसे राज्य के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश की 55 फीसदी जमीन डूबी

सरदार सरोवर बांध में सबसे ज्यादा जमीन मध्यप्रदेश की ही डूबी है जो 55 फीसदी के लगभग है। बावजूद इसके इस बांध का लाभ सबसे ज्यादा गुजरात को हो रहा है। मध्यप्रदेश में लगभग 19,628 हेक्टेयर भूमि सरदार सरोवर के जलाशय में डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें करीब 2,809 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। लगभग 178 गांव परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं। निजी भूमि और मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि राजस्व भूमि, वन भूमि और खनिज क्षेत्र के मुआवजे को लेकर मध्यप्रदेश और गुजरात के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। डूब का प्रभाव मुख्य रूप से धार, बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर जिलों के गांवों पर पड़ा है। हजारों परिवारों का पुनर्वास किया गया। बड़ी मात्रा में कृषि भूमि जलाशय में समा गई। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अनेक गांव प्रभावित हुए। पुनर्वास, मुआवजा और बैकवॉटर स्तर को लेकर वर्षों से विवाद और कानूनी मामले चलते रहे हैं।

सवाल हजारों विस्थापितों का भी है

विवाद केवल पैसों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न उन हजारों परिवारों का है, जिन्होंने सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपनी जमीन, घर और आजीविका खोई। परियोजना का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्यप्रदेश में है और सर्वाधिक विस्थापन भी यहीं हुआ। ऐसे में यदि राज्य अपने वित्तीय और पुनर्वास संबंधी अधिकारों पर पर्याप्त मजबूती से दावा नहीं रख पाया, तो इसका सीधा असर प्रभावित परिवारों के हितों पर पड़ सकता है।

कर्ज में डूबी सरकार और अपने हिस्से का पैसा भी दे आये

एक तरफ मोहन सरकार कर्ज की बैशाखी पर चल रही है वहीं दूसरी तरफ अपने हक के पैसों को लेने में नाकाम साबित हुई। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार को बार-बार कर्ज लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद प्रदेश को 550 करोड़ रूपये का भुगतान करने का समझौता होना प्रदेश के साथ अन्याय है। गुजरात सरकार पर जो लेनदारी बन रही थी वह मप्र के हक था और उसके साथ-साथ उन परिवारों का भी था जिनके घर उजड़े हैं, जिनकी जमीनें डूबी हैं। लेकिन सरकार ने तो न अपना हित देखा और न ही विस्थापितों का दुख-दर्द समझा।

मछली पालन बना आत्मनिर्भरता का नया आधार

(पेज 1 का शेष)

यह सोच केवल किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। जब किसान खेती के साथ मत्स्य पालन को अपनाते हैं, तब उन्हें पूरे वर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और आर्थिक जोखिम भी कम हो जाता है।

भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा

मछली पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अपेक्षाकृत कम पूंजी और सीमित भूमि में भी सफलतापूर्वक शुरू किया जा सकता है। जिन किसानों के पास छोटे या मध्यम आकार के तालाब हैं, वे उनका उपयोग मत्स्य पालन के लिए कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नहरों, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों का भी वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। बाजार में मछली की लगातार बढ़ती मांग तथा लोगों में पौष्टिक आहार के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को और अधिक मजबूत किया है। प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर मछली आज संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। मत्स्य पालन केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके साथ अनेक सहायक गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करती हैं। मत्स्य बीज उत्पादन, हैचरी संचालन, संतुलित मत्स्य आहार निर्माण, मछली परिवहन, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने लगा है और शहरों की ओर पलायन में भी कमी आने की संभावना बढ़ी है।

उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि

छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के लिए दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण, संतुलित आहार, जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा विपणन संबंधी व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। इससे मत्स्य पालकों की तकनीकी दक्षता बढ़ती है और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। राज्य सरकार प्रगतिशील मत्स्य पालकों को अन्य राज्यों के सफल मत्स्य पालन मॉडल का अध्ययन कराने के लिए अध्ययन भ्रमण पर भी भेजती है। इससे उन्हें आधुनिक तकनीकों, बेहतर प्रबंधन और नवाचारों को समझने का अवसर मिलता है, जिन्हें वे अपने क्षेत्र में अपनाकर उत्पादन और आय दोनों बढ़ा सकते हैं।

आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा

मत्स्य सहकारी समितियों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इससे छोटे मत्स्य पालकों को भी बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने में सहायता मिलती है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नाव और जाल उपलब्ध कराकर पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय को भी मजबूत किया जा रहा है, जबकि छोटे फुटकर विक्रेताओं को आइस बॉक्स, तराजू तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण मछली उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए स्पॉन संवर्धन तथा झींगा सह मछली पालन जैसी विशेष योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने तथा अधिक लाभकारी मत्स्य उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आकर्षक अनुदान उपलब्ध कराया

मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत नए तालाबों के निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना, आधुनिक उपकरणों की खरीद तथा वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए आकर्षक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज, संतुलित आहार, जल गुणवत्ता प्रबंधन और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धतियाँ उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही सजावटी मछली पालन तथा जलाशयों में केज कल्चर जैसी नई तकनीकों ने स्वरोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। इन क्षेत्रों में कम निवेश के साथ अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकार विपणन व्यवस्था को भी मजबूत बना रही है। शीत संयंत्र, प्रशीतित वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा तथा लाइव फिश सेंटर जैसी सुविधाओं से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें दूर-दराज के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है। इससे मत्स्य पालकों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होते हैं।

आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित होता है

मत्स्य पालकों की सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मछली पकड़ने की प्रतिबंधित अवधि के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बचत सह राहत योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क समूह बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना, मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में मत्स्य पालकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का सामाजिक और आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित होता है। आज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मत्स्य पालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला प्रभावी माध्यम बन चुका है। यह किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार की योजनाएँ, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बेहतर विपणन व्यवस्था मिलकर मत्स्य क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा रही हैं। यदि इस क्षेत्र में उपलब्ध योजनाओं का व्यापक लाभ उठाया जाए और अधिक से अधिक किसान तथा युवा मत्स्य पालन को अपनाएँ, तो यह न केवल उनकी आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। वास्तव में नीली क्रांति केवल मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का अभियान नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखने वाला परिवर्तनकारी आंदोलन है।

संसदीय मर्यादा के शिखर पुरुष रहे हैं कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

कमलनाथ इसी गौरवशाली परंपरा के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनकल्याण के मुद्दों पर सरकार को सही राह दिखाना और स्वस्थ चर्चा के जरिए देशहित में रास्ते निकालना है। उनके कार्यकाल में सदन केवल हंगामे का केंद्र नहीं, बल्कि जन सरोकारों के फैसलों की कर्मभूमि हुआ करता था। एक कुशल प्रशासक और राजनेता के रूप में उन्होंने हमेशा माना कि नीतियां बनाने के लिए गंभीर चिंतन और व्यापक संवाद की जरूरत होती है। उन्होंने सदन में रहते हुए हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हर बिल, हर बजट और हर नीति पर खुलकर बातचीत हो, ताकि जनता के हित के फैसलों को सही दिशा मिल सके। आज के नेताओं को नेहरू जी, इंदिरा जी और अटल जी जैसे नेताओं से सीख लेने की जरूरत है। जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान किया और लोकतंत्र की परिभाषा को सारगर्भित किया।

एक दूरदर्शी सोच, जो हमेशा जनता के साथ रही

कमलनाथ की राजनीति का सबसे खूबसूरत पहलू ही यही रहा कि उनके लिए राजनीति कभी व्यक्तिगत शह-मात का खेल नहीं रही। उनकी सोच हमेशा इस बात पर केंद्रित रही कि व्यवस्था का आखिरी पहिया भी घूमना चाहिए और उसका लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए।

वक्त की पुकारः फिर से लौटानी होगी वह गरिमा

कमलनाथ का संसदीय सफर हमें याद दिलाता है कि सत्ता आती-जाती रहती है, पद बदलते रहते हैं, लेकिन जो मर्यादा एक नेता सदन में स्थापित करता है, वह इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो जाती है। आज के बदलते और बिखरते संसदीय मूल्यों के बीच, कमलनाथ का व्यक्तित्व एक रोशनी की तरह है।

दलगत राजनीति से ऊपर कमलनाथ से मार्गदर्शन की दरकार

आज की इस बिखरी हुई और वैचारिक रूप से बंटी हुई राजनीति में कमलनाथ एक ऐसे वटवृक्ष की तरह हैं, जिनकी छत्रछाया में हर दल का नेता खुद को सुरक्षित और समृद्ध महसूस कर सकता है। आज के दौर के जनप्रतिनिधियों- चाहे वे कांग्रेस के उभरते हुए युवा चेहरे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, सभी को दलगत राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर कमलनाथ से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनके पास बैठकर देशसेवा का ककहरा सीखना चाहिए। एक ऐसा राजनेता जिसने दशकों तक दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर मध्य प्रदेश की माटी तक को बहुत करीब से देखा है, उनके पास अनुभवों का वह अनमोल खजाना है जिसे किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता। आज की युवा पीढ़ी के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे धुर विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद सदन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखी जाती है। भाजपा के भी जनप्रतिनिधियों को उनके प्रशासनिक चातुर्य और जनकल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन की कला से सीख लेकर देशहित में अपनी सोच को और अधिक व्यापक और समृद्ध बनाना चाहिए। आखिरकार, लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है कि जब बात राष्ट्र निर्माण और जनता के कल्याण की हो, तो वरिष्ठों का अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। कमलनाथ का द्वार हमेशा हर उस व्यक्ति के लिए खुला मार्गदर्शन है, जो मर्यादा, विकास और जनहित की राजनीति को आगे ले जाना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को उनके जीवन से यह सीखना बेहद जरूरी है कि लोकतंत्र में बहस की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बनाए रखकर ही हम वास्तव में जनता की सेवा कर सकते हैं। "सदन सिर्फ दीवारों और कुर्सियों से नहीं बनता, वह वहाँ बैठे नेताओं के आचरण और मर्यादा से जीवंत होता है। कमलनाथ ने उस जीवंतता को हमेशा संजोकर रखा है।

आज का कड़वा सचः शोर के बीच सिसकती मर्यादाएँ

आज जब हम देश की विधानसभाओं और संसद के सत्रों को देखते हैं, तो एक अजीब सी कसक महसूस होती है। आजकल सदन के सत्र बहुत छोटे होते जा रहे हैं और जो होते भी हैं, वे चर्चा के बजाय हंगामे और व्यक्तिगत हमलों की भेंट चढ़ जाते हैं।

बौद्धिक विमर्श का अभावः पहले विपक्ष सरकार की नीतियों से सीखता था और सरकार विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का सम्मान करती थी। आज यह स्वस्थ परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है।

जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसानः यह सोचना बेहद चिंतनीय है कि जनता के जिस पैसे से ये सत्र चलते हैं, वह बिना किसी ठोस फैसले या चर्चा के सिर्फ शोर-शराबे में बह जाता है। जब सत्रों में सार्थक चर्चा ही नहीं होगी, तो जनता के हित के कानून और नीतियां कैसे बनेंगी?

भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 40 वर्षों से हो रहा लोहा चोरी

(पेज 1 का शेष)

पहले पिता दलवीर सिंह उर्फ़ वीरा सिंह करता था, पिता के मरने के बाद बेटा इन्द्रजीत सिंह उर्फ छोटू इस काम को अंजाम दे रहा है। पिता दलवीर सिंह पहले सूअर काट-काट कर बेचता था। फिर कबाड़ के धंधे में उतर गये। फिर भिलाई स्टील प्लांट में सी.आई.एस.एफ. और पुलिस की मदद से लोहा चोरी का साम्राज्य खड़ा कर लिया। देखते-देखते 1500 ट्रकों की बहुत बड़ी हेवी ट्रांसपोर्ट कम्पनी बना ली और हेवी ट्रांसपोर्टर बन गया। इन्द्रजीत सिंह जितने भी दो नम्बर के काम करता है उसके लिए ड्राइवरों के नाम पर ही ट्रक खरीद लेता है, जिससे जब चोरी का लोहा पकड़ा जाय तो ड्राईवर पकड़ा जाय। इन्द्रजीत उर्फ़ छोटू इस लोहा चोरी के धंधे को बड़े शातिराना अंदाज से अंजाम दे रहा है। यह लोहा चोर ट्रांसपोर्टर छत्तीसगढ़ पुलिस के बहुत से अधिकारियों को साल में करोड़ों रुपयों की घूस देता है। एक दबंग आईपीएस अधिकारी के आंखों के अस्पताल में लगभग पांच करोड़ का मेटेरियल इस ट्रांसपोर्टर ने मुफ्त में पहुँचाया। जिसमें ईंट, मुरम, रेत, सीमेंट, छड़ आदि मेटेरियल शामिल था। आज की तारीख में यह आलीशान आँखों का अस्पताल चल रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के मार्केटिंग डिविजन के अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है और नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। यह ट्रांसपोर्टर थाना भट्ठी के सभी पुलिस वालों को घूस देता है। मतलब यह है कि दुर्ग जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारी इस लोहा चोरी के धंधे में लिप्त हैं। इस ट्रांसपोर्टर का आलिशान मकान कोहका में है। कम्पनी ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में और छत्तीसगढ़ ट्रक टेलर एसोसिएशन का आफिस खुर्सीपार में है। इस यूनियन का इंद्रजीत अध्यक्ष है। यूनियन की पर्ची प्रति ट्रक 1500 रूपये की काटी जाती है। बाहरी गाड़ियों से मनमानी रकम वसूल की जाती है। लगभग 1500 ट्रक, ट्राला, ट्रिप टेलर तो अकेली हेवी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पास हैं, हजारों ट्रक की आवाजाही भिलाई स्टील प्लांट से होती है।

पुलिस ने जप्त किया 250 टन लोहा, 15 लोगों की गिरफ्तारी

मई 2026 में दुर्ग पुलिस ने 'एके ट्रेडर्स' नामक कबाड़ यार्ड पर छापा मारकर 250 टन से अधिक चोरी का लोहा बरामद किया। जिसकी कीमत करोड़ों में है। साथ ही 15 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इसमें स्टी2ल प्लां ट के कर्मचारी भी थे। जुलाई 2026 में पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर हिमांशु भूषण मलिक और इंजीनियरिंग एसोसिएट मनोज देवांगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में अब तक 15 से अधिक आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस रैकेट का भंडाभोड़ होने के बाद तहलका मच गया था। लोहा चोरी बड़े ही शातिर तरीके से होता था। ट्रक ऑपरेटर प्लांट से निकलने वाले कचरे (फ्लाई ऐश/डस्ट) के नीचे भारी मात्रा में स्टील प्लेट, बीम और लोहे के स्क्रैप को छिपा देते थे।

रसूखदार नेताओं और अफसरों से सांठगांठ

बताया जा रहा है कि इन्द्रजीत सिंह उर्फ छोटू का प्रदेश के बड़े-बड़े रसूखदार नेताओं और अधिकारियों से सांठगांठ है। और इनका संरक्षण भी प्राप्ते है, जो किसी न किसी रूप से इन्द्रजीत सिंह की मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के बेटे की शादी का पूरा खर्च इंद्रजीत सिंह और अनिल सिंह द्वारा उठाया गया था। अनिल सिंह भी कई अवैध धंधों में शामिल है।

सम्पादकीय

कर्ज, विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन की चुनौती

किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति उसके वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करती है। सरकारें विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के निर्माण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय-समय पर ऋण लेती हैं। यदि यह ऋण उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के लिए लिया जाए और उससे राज्य की आय में वृद्धि हो तो इसे आर्थिक विकास का माध्यम माना जाता है। किंतु जब कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने लगे और उसके अनुपात में राजस्व तथा आर्थिक क्षमता का विस्तार न हो, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर भी इसी प्रकार की बहस चल रही है।

मध्य प्रदेश देश के बड़े राज्यों में शामिल है, जहाँ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई तथा शहरी विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़े निवेश की आवश्यकता रहती है। सरकार का तर्क है कि विकास परियोजनाओं को गति देने, अधूरी योजनाओं को पूरा करने तथा जनता को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए ऋण लेना आवश्यक है। सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएँ, बिजली व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएँ और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय भविष्य में राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इस दृष्टि से सीमित और योजनाबद्ध ऋण लेना असामान्य नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर लगातार बढ़ता कर्ज राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है। किसी भी ऋण के साथ ब्याज और मूलधन चुकाने की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। यदि राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा केवल ऋण चुकाने में खर्च होने लगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। इसका प्रभाव वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है, क्योंकि अंततः सरकारी ऋण का भार करदाताओं पर ही आता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कर्ज लेना समस्या नहीं है बल्कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ऋण से ऐसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो जो भविष्य में आय और रोजगार बढ़ाएँ, तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। इसके विपरीत यदि ऋण का बड़ा हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च या अल्पकालिक राजनीतिक घोषणाओं पर व्यय हो जाए तो राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए सरकार को प्रत्येक ऋण के उपयोग का स्पष्ट और पारदर्शी विवरण जनता के सामने रखना चाहिए।

मध्य प्रदेश में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण आधारभूत ढाँचे पर भी बड़े निवेश की जरूरत है। ऐसे में सरकार के सामने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। केवल कर्ज लेकर विकास की गति बनाए रखना दीर्घकाल में टिकाऊ समाधान नहीं माना जा सकता। सरकार को अपने राजस्व स्रोतों में वृद्धि पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित करना, कर संग्रह प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग तथा सरकारी व्यय में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जैसे उपाय राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और पारदर्शिता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लिया गया ऋण वास्तव में विकास का माध्यम बने।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष, अर्थशास्त्रियों और नागरिक समाज की यह जिम्मेदारी भी है कि वे सरकार की वित्तीय नीतियों पर रचनात्मक चर्चा करें। केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय यह देखा जाना चाहिए कि ऋण की राशि कहाँ खर्च हो रही है, उससे जनता को कितना लाभ मिल रहा है और भविष्य में उसकी वापसी की क्या योजना है। वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की विश्वसनीयता का आधार होती है।

सियासी गहमागहमी

नरोत्तम का दतिया से टिकट कटना आखिर क्या वजह है?

मध्य प्रदेश की राजनीति में वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट न मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय तक दतिया का प्रतिनिधित्व करने वाले और राज्य सरकार में गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके मिश्रा का नाम संगठन के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा है। ऐसे में उनका टिकट कटना कई राजनीतिक संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा समय-समय पर संगठन में बदलाव और नए चेहरों को अवसर देने की रणनीति अपनाती रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरण, संगठन की आंतरिक समीक्षा, क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ और जीत की संभावनाओं का आकलन भी टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ जानकार इसे पार्टी की पीढ़ीगत परिवर्तन की रणनीति से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ इसे स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का परिणाम मानते हैं। हालाँकि भाजपा नेतृत्व ने टिकट वितरण को संगठन का सामूहिक निर्णय बताया है और किसी एक कारण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसलिए टिकट कटने के वास्तविक कारणों को लेकर केवल राजनीतिक अटकलें ही लगाई जा रही हैं। स्पष्ट निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब पार्टी स्वयं इस निर्णय के पीछे के कारणों पर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी दे।

ट्रेन यात्रा पर ले रहे राजनेता चुटकी

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की एक ही ट्रेन में हुई यात्रा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। दोनों नेताओं की मुलाकात और सहज बातचीत की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की टिप्पणियाँ और चुटकियाँ सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक सौहार्द का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच बढ़ती राजनीतिक शालीनता पर व्यंग्य कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों का सौहार्दपूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। संसद से लेकर विधानसभा तक अनेक अवसर ऐसे रहे हैं, जब वैचारिक मतभेद रखने वाले नेता निजी स्तर पर सम्मान और आत्मीयता बनाए रखते हैं। ऐसे में किसी सार्वजनिक यात्रा के दौरान दो नेताओं का साथ दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। हालाँकि चुनावी माहौल में हर छोटी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। यही कारण है कि इस यात्रा को लेकर भी सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में हास्य, व्यंग्य और अटकलों का दौर जारी है। लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह रहें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में संवाद और शिष्टाचार भी कायम रहे। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की पहचान है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है।
जब सोनम वांगचुक जी अहिंसक अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर मंतर से हटाना गलत था। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, और छात्र आत्महत्याएँ भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी बल की मात्रा भारत के छात्रों को, और हममें से उन लोगों को जो उन्हें प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भाजपा सरकार से कोई काम नहीं संभल रहा।
मध्य प्रदेश में अब 75 हजार सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ प्रबंधन में गड़बड़ी सामने आ रही है। इस कारण रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मचारी आसानी से जीपीएफ नहीं निकाल पा रहे।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

उत्तराखंड की राजनीति का एक सशक्त अध्याय हैं हरीश रावत

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का नाम एक अनुभवी, सरल और जनसरोकारों से जुड़े राजनेता के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। उत्तराखंड के विकास, किसानों, युवाओं तथा पर्वतीय क्षेत्रों के हितों की आवाज़ बुलंद करने वाले नेताओं में उनका विशेष स्थान है। अपनी सादगी, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसंपर्क के कारण वे राज्य की राजनीति में आज भी प्रभावशाली माने जाते हैं। हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1948 को उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के अल्मोड़ा जिले के मोहनरी गाँव में हुआ। उनका बचपन पहाड़ी परिवेश में बीता, जहाँ उन्होंने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को निकट से देखा। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन से ही सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। युवावस्था में ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और संगठन के लिए समर्पित होकर कार्य करना आरम्भ किया। राजनीति में उनकी पहचान एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में बनी। उन्होंने कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपनी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहने तथा जनसमस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के कारण वे शीघ्र ही राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि में आए। इसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला और वे संसद पहुँचे। सांसद के रूप में उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सड़क, शिक्षा, सिंचाई तथा पर्यटन से जुड़े अनेक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

हरीश रावत ने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। वे विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, जहाँ उन्होंने कृषि, श्रम, संसदीय कार्य तथा जल संसाधनों जैसे क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में योगदान दिया। प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के कारण कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपीं। उनका कार्यकाल एक मेहनती और सक्रिय मंत्री के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य की राजनीति में हरीश रावत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब सामने आई जब वे वर्ष 2014 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी अनेक प्रयास किए। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास योजनाओं को गति देने का प्रयास किया। हालाँकि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिली। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बाद में न्यायालय के निर्णय के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री बने। यह दौर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखा और जनता के बीच अपनी सक्रियता जारी रखी। राजनीतिक जीवन में उन्हें अनेक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा, किन्तु उन्होंने संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा। चुनावों में जीत और हार दोनों का अनुभव करने के बावजूद वे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद उनकी विशेष पहचान है। वे युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सेवा और जनभागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो हरीश रावत का राजनीतिक जीवन संघर्ष, सेवा और जनसंपर्क का प्रतीक है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास, किसानों के कल्याण, ग्रामीण उत्थान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य किया। एक जननेता, प्रशासक और अनुभवी राजनेता के रूप में उनका योगदान भारतीय राजनीति तथा विशेष रूप से उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि निरंतर परिश्रम, जनता से जुड़ाव और लोकतांत्रिक आस्था के बल पर राजनीति में दीर्घकाल तक प्रभावी भूमिका निभाई जा सकती है।

छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अधोसंरचना में रचा नया विकास अध्याय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान ही नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के दीर्घकालीन और समग्र विकास की मजबूत नींव भी रखी है. ऊर्जा, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अधोसंरचना के क्षेत्रों में बीते ढाई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा क्षेत्र गंभीर संकट से जूझ रहा था। भाजपा सरकार ने उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों स्तरों पर दीर्घकालिक रणनीति अपनाई। राज्य में आयोजित एनर्जी समिट के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रतिदिन 500 से अधिक नए सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों का बिजली बिल शून्य अथवा अत्यंत कम हो गया है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ कर आम लोगों को राहत दी गई है। किसानों के लिए सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और कृषि विद्युत सब्सिडी में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खनिज संपदा का उपयोग केवल राजस्व अर्जन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका लाभ खनन प्रभावित क्षेत्रों और स्थानीय नागरिकों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय जिला खनिज न्यास में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आईं, जबकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने रिकॉर्ड 16 हजार 737 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित किया है। खनिज ऑनलाइन 2.0 एवं डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू कर खनन क्षेत्र में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। अब तक डीएमएफ के माध्यम से प्रदेश को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिससे 82 हजार से अधिक विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। अवैध खनन के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई हैं तथा ड्रोन, जीपीएस और आरएफआईडी आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के भविष्य के लिए आवश्यक क्रिटिकल एवं स्ट्रेटजिक मिनरल्स के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लीथियम सहित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई है। महासमुंद जिले में हीरे मिलने को उन्होंने प्रदेश की नई संभावनाओं का संकेत बताया।

इंदौर मॉडल से बदलेगी हावड़ा की तस्वीर

-अमित राय

जगत प्रवाह. इंदौर/हावड़ा। हावड़ा नगर निगम के प्रतिनिधिमंडल के साथ पश्चिम सरकार में संसदीय कार्य तथा नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों के राज्य मंत्री उमेश राय ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का दौरा कर वहां की आधुनिक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर में लागू विभिन्न स्वच्छता मॉडलों और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन प्रणाली का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली को करीब से समझा। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूस-रीयूज-रीसायकल (3आर) स्टेशन, भारत के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट (ऐनवेर ऐनविरो) तथा नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया। वहीं अधिकारियों ने वैज्ञानिक कचरा निस्तारण, संसाधनों के पुनर्चक्रण और आधुनिक स्वच्छता प्रबंधन की तकनीकों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। राज्य मंत्री ने कहा कि इंदौर ने जनभागीदारी, आधुनिक तकनीक और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल स्थापित किया है। इस अध्ययन दौरे से प्राप्त अनुभवों और तकनीकी जानकारियों का उपयोग हावड़ा की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। इन सफल मॉडलों को अपनाने से हावड़ा में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और नागरिक सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

भाजपा ने अपने ही नगर परिषद उपाध्यक्ष को थमाया नोटिस

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर परिषद कार्यालय के सामने कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होना भाजपा के नगर परिषद उपाध्यक्ष जयंत राजा कौशल के लिए राजनैतिक विवाद का कारण बन गया। भाजपा ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना। भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल बारंगे ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाध्यक्ष को भी भेजी। टिमरनी नगर परिषद में भाजपा का बहुमत है परिषद अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज भी भाजपा से है। ऐसे में पार्टी ने अपने ही उपाध्यक्ष का कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के साथ मंच साझा करना धरने में शामिल होना गंभीर अनुशासनहीनता माना है। मुझे नोटिस नहीं मिला

मुझे अभी मंडल अध्यक्ष जी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है।

-जयंत राजा कौशल, उपाध्यक्ष, नगर परिषद, टिमरनी

पार्टी विरोध बर्दाश्त नहीं संगठन सर्वोपरि है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद उपाध्यक्ष जयंत राजा कौशल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

-अतुल बारंगे, मंडल अध्यक्ष, भाजपा

छतरपुर में विस्थापितों का 'चिता आंदोलन' तेज, भूख हड़ताल जारी

-संवाददाता

जगत प्रवाह. भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण बेघर हुए लोगों की लड़ाई अब बेहद गंभीर रूप ले चुकी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, एनटीपीसी, मझगांव, रूंज और नौगुवा जैसी बड़ी परियोजनाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार और विस्थापितों के सही पुनर्वास की मांग को लेकर 'जय किसान संगठन' के बैनर तले चल रहा 'चिता आंदोलन' दिन-ब-दिन और तेज होता जा रहा है। इस क्रम में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का भूख हड़ताल जारी है, जिससे स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और स्वास्थ्य को लेकर चिंताए भी बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार भूख हड़ताल पर बैठे अमित भटनागर की सेहत में तेजी से गिरावट आ रही है। आंदोलनकारियों के मुताबिक, उनका वजन करीब 6 किलोग्राम तक घट चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता के समर्थन में आंदोलन स्थल पर मौजूद प्रभावित परिवारों ने भी अपना विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शन स्थल पर चूल्हा नहीं जलाया गया, जिसके कारण लगभग 500 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भूखे रहने को मजबूर हुए। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले चार सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

नशे के विरुद्ध निर्णायक युद्धः ड्रग्स माफियाओं पर बढ़ा प्रहार

किशन भावनानी
एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार भारत ने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध समयबद्ध रणनीति अपनाकर विजन 2026 के माध्यम से नक्सलवाद को निर्णायक रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, उसी प्रकार अब केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध भी एक स्पष्ट, बहुस्तरीय और समयबद्ध अभियान प्रारंभ किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 26 जून 2026 को नार्को- कोऑर्डिनेशन सेंटर (नार्कॉर्ड) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में जारी नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध घोषितरणनीतिक युद्ध का रोडमैप है। गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत 3डी रणनीति-डिटेक्ट, डिसट्रप्ट और डिस्ट्रॉय, इस नई नीति का संचालन सिद्धांत है। डिटेक्ट का अर्थ है अत्याधुनिक तकनीक, खुफिया सूचनाओं और डेटा विश्लेषण के माध्यम से नेटवर्क की प्रारंभिक पहचान करना।डिसट्रप्ट का उद्देश्य अपराधी नेटवर्क की गतिविधियों को बीच में ही रोक देना है ताकि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला संचालित न कर सकें। डिस्ट्रॉय का आशय है अपराधियों के आर्थिक स्रोत, अवैध संपत्तियों, उत्पादन केंद्रों और पूरे नेटवर्क को स्थायी रूप से समाप्त करना। यह रणनीति केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अपराध की संरचना को ध्वस्त करने पर आधारित है।सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले तीन वर्ष यह तय करेंगे कि भारत नशे के वैश्विक नेटवर्क के सामने झुकेगा या उसे निर्णायक रूप से परास्त करेगा। आज मादक पदार्थों की तस्करी पारंपरिक अपराध की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है। यह आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से गहराई से जुड़ चुकी है। दुनियाँ के अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ड्रग्स का पैसा अक्सर आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की वित्तीय जीवनरेखा बनता है। इसी कारण भारत सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि ड्रग्स केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर प्रश्न है। यह दृष्टिकोण भारत की एंटी नारकोटिक्स नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है।

नार्कॉर्ड की 10वीं बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन वर्ष यह निर्धारित करेंगे कि नशा भारत पर हावी होगा या भारत नशे पर विजय प्राप्त करेगा। यह केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का सार्वजनिक संकल्प है। इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्रीय जांच एजेंसियों, सुरक्षा बलों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस चुनौती को पूरे शासन तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी मान रही है।

नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 की सबसे बड़ी विशेषता इसका त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है।पहला लक्ष्य है डिमांड रिडक्शन अर्थात समाज विशेषकर युवाओं में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना। दूसरा लक्ष्य है सप्लाई रिडक्शन अर्थात तस्करी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करना। तीसरा लक्ष्य है हार्म रिडक्शन एवं पुनर्वास,अर्थात नशे के शिकार व्यक्तियों को अपराधी नहीं बल्कि उपचार और पुनर्वास के पात्र नागरिक मानते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना। यही संतुलित दृष्टिकोण आधुनिक वैश्विक ड्रग नीति का भी आधार माना जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल ड्रग्स पकड़ने की नीति नहीं है बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने की रणनीति प्रस्तुत करता है। पहले जहां कार्रवाई का मुख्य केंद्र ड्रग्स की बरामदगी और छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित रहता था, वहीं अब लक्ष्य पूरे अंतरराष्ट्रीय कार्टेल, उनके वित्तीय स्रोत, हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग चैनल, डार्कनेट प्लेटफॉर्म और विदेशी संचालकों तक पहुंचना है। यह नेटवर्क आधारित प्रवर्तन भारत की जांच प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकता है। बीते कुछ वर्षों में ड्रग्स तस्करी का स्वरूप तेजी से बदला है। अफीम, चरस और गांजा जैसे पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथमफेटामाइन, एमडीएमए और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थ,तेजी से फैल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्हें छोटे-छोटे गुप्त प्रयोगशालाओं में तैयार किया जा सकता है, इन्हें छिपाना अपेक्षाकृत आसान होता है और इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिजिटल माध्यमों से संचालित होता है। यही कारण है कि विजन डॉक्यूमेंट में सिंथेटिक ड्रग्स को विशेष खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।

पहले जहां कार्रवाई का मुख्य केंद्र ड्रग्स की बरामदगी और छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित रहता था, वहीं अब लक्ष्य पूरे अंतरराष्ट्रीय कार्टेल, उनके वित्तीय स्रोत, हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग चैनल, डार्कनेट प्लेटफॉर्म और विदेशी संचालकों तक पहुंचना है। यह नेटवर्क आधारित प्रवर्तन भारत की जांच प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकता है। बीते कुछ वर्षों में ड्रग्स तस्करी का स्वरूप तेजी से बदला है। अफीम, चरस और गांजा जैसे पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथमफेटामाइन, एमडीएमए और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थ,तेजी से फैल रहे हैं।

डिजिटल युग ने ड्रग तस्करी को नई दिशा दी है। डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी ने अपराधियों को ऐसी गुमनामी प्रदान की है जिससे पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के लिए उन्हें पकड़ना कठिन हो गया है। आज कई अंतरराष्ट्रीय ड्रग सौदे बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ऑनलाइन तय होते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यमों से होता है। भारत की नई नीति इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल निगरानी, डेटा इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल देती है।

भारत सरकार ने इस अभियान में वित्तीय कार्रवाई को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक संगठित अपराध का सबसे बड़ा आधार उसका आर्थिक संसाधन होता है। यदि तस्करों की संपत्ति, बैंक खाते, हवाला नेटवर्क और निवेश जब्त कर दिए जाएं तो उनका अपराध लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसी सोच के तहत संबंधित कानूनों के माध्यम से अवैध संपत्तियों की कुर्की, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तथा आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति को मजबूत किया जा रहा है।राज्यों में गठित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स इस अभियान की जमीनी शक्ति होगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह टास्क फोर्स नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य केवल पुलिस कार्रवाई करना नहीं बल्कि विभिन्न विभागों, खुफिया एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बलों, राजस्व विभाग और अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। इससे सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता बढ़ने की संभावना है।

नार्कॉर्ड की चार स्तरीय संरचना, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर, भारत जैसे विशाल और संघीय देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सक्रिय होते हैं लेकिन उनके तार अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक एकीकृत समन्वय ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। बैठक के दौरान देशभर में लगभग 2,09,500 किलोग्राम अवैध नशीले पदार्थों का विनाश किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,000 करोड़ रूपए बताई गई। यह केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ पुनः अवैध बाजार में नहीं लौटेंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई के परिणाम अब अधिक व्यापक रूप में सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ कर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी संस्थागत क्षमता भी मजबूत की है। भारत की पश्चिमी और पूर्वोत्तर सीमाएं लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स मार्गों से प्रभावित रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में संस्थागत उपस्थिति बढ़ाना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

ड्रग्स के विरुद्ध संघर्ष केवल गृह मंत्रालय या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वित्त, सीमा प्रबंधन, विदेश नीति, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य मंत्रालयों सहित पूरे शासन तंत्र की साझा जिम्मेदारी होगी। जब 44 केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और विभिन्न एजेंसियां एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करेंगी, तभी व्यापक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल दमनात्मक कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। यदि समाज में जागरूकता, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नशा विरोधी अभियान, परिवारों की सहभागिता मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पुनर्वास केंद्रों की प्रभावशीलता नहीं बढ़ेगी तो केवल गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में मांग कम करने और पुनर्वास को समान महत्व दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग्स के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ड्रग्स उत्पादन, तस्करी, वित्तपोषण और वितरण अक्सर कई देशों में फैला होता है। इसलिए प्रत्यर्पण, साझा खुफिया जानकारी, सीमापार जांच और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि किसी भी विजन डॉक्यूमेंट की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि राज्यों के बीच समन्वय मजबूत नहीं होगा, जांच समयबद्ध नहीं होगी, न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं होगा और पुनर्वास व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए आने वाले तीन वर्षों में वास्तविक परीक्षा केवल नीति की नहीं बल्कि उसके प्रभावी कार्यान्वयन की होगी।

बदलता मौसम, बढ़ती चिंता: भारत के वर्तमान मौसम के हालात का सच

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

विज्ञान की निरंतर भागदौड़ तथा मानव का भौतिकवाद और असंतुष्ट लोभ, प्राकृतिक संकलनों-संसाधनों की तीव्रता से नष्ट करने के कारण मौसम में जो बदलाव हुआ है वह बेहद चिन्ता का विषय है। इस साल फरवरी मार्च में ही कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ी। गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण भागों में लू जैसी स्थिति देखी गई थी। मई-जून में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में बारिश होती रहीं। मई-जून के माह में जब लू के थपेड़े चेहरे को लाल करने लगता है तब बर्फीली हवाएं चल रही थी और पंखे की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मौसम के दिनोंदिन आ रहे बदलाव को सामान्य तो नही कह सकते। दरअसल यह एक भीषण समस्या है जिसे झुठलाया नहीं सकता। समूची दुनिया इसके दुष्प्रभाव से अछूती नहीं है। इस वर्ष यूरोप के आठ देशों में औसतन पिछले कई वर्षो के मुकाबले लगभग 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश और थाईलैंड में तापमान ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन, जापान, म्यांमार और वियतनाम में कमोबेश यही स्थिति रही। मौसम विज्ञानी भी अचंभित हैं। वैसे हैरानी की बात आजकल नही रही क्योंकि न तो गर्मियां गर्मियों की तरह रही और न तो सर्दी सर्दियों की तरह। दस साल पहले के मौसम के तुलना में आजकल का मौसम पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। मार्च के महीने में भारत के कई राज्यों में भारी बारिश देखी गई। वर्षा से तापमान घटता है, लेकिन फरवरी महीने में पिछले वर्ष की तुलना में कम पानी गिरने से तापमान बढ़ा। देश के कई हिस्से फसलों के लिए जनवरी-फरवरी में बारिश के लिए तरसते रहे। लेकिन अप्रेल-मई में जब खेतों में गेहूं पक चुकी थी तब बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि खेतों में ही फसल बिछ गई। यह खतरे की घंटी है। बदलते मौसम की मार से प्रकृति के साथ साथ हमारे जीवन के कोई पहलू अछूता नहीं बचा है। हमारा रहन सहन, भोजन, स्वास्थ्य और कृषि इस रुप से प्रभावित हुई है। कृषि उत्पादन में आ रही कमी, सुखा और भूमि के बंजर होने की गति में हो रही बढ़ोतरी इसका जीता जागता सबूत है। वैज्ञानिक शोध और अध्ययन ने इस तथ्य को प्रमाणित भी कर दिया है। मौसम के बदलाव के कारण मनुष्य संक्रमण की चपेट में है। नतीजन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़, चक्रवात, तूफान आदि आपदाओं में बढ़ोतरी उसी का नतीजा है।

मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है जो मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही एयरोसॉल सल्फेट की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जमीन और जल दोनों का तापमान बढ़ रहा है। अलनीनो के कारण भी तापमान पर प्रभाव पड़ा है। जमीन की कटाई की वजह से जमीन से वाष्पीकरण में कमी आई है। भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जून 2020 में जलवायु परिवर्तन पर आई रिपोर्ट में कहा गया है। 1986 से 2015 के बीच गर्म दिनों का तापमान 0.63 डिग्री सेल्सियस और सर्द रातों का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर यही रुझान आगे भी रहा तो गर्म दिनों का तापमान 4.7 डिग्री और सर्द रातों का तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्म दिनों की संख्या 5.5 फीसदी तक और गर्म रातों की संख्या 70 फीसदी तक बढ़ना तय है जो बेहद चिंताजनक है।

यह सही है कि प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारकों व कारणों के पीछे इंसानी गतिविधियां भी कम जिम्मेदार नहीं। अब समय की मांग है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर तत्काल लगाम लगे जिससे औसत तापमान बढ़ोतरी पर अंकुश लगे।

मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ!

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर अब थम गया है, परिणाम सामने हैं और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। जहाँ कुछ युवाओं को उनके मनपसंद कॉलेज और कोर्स मिल गए हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अपनी उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने से थोड़े निराश हैं। आज हम इन्हीं युवाओं से बात करेंगे। याद रखिए, जीवन संभावनाओं से भरा है। अपनी कथित असफलता को एक अनुभव के तौर पर लें और इससे सीखकर सफलता की ओर बढ़ें। खुद से बस इतना कहें: "मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ!" सवाल यह नहीं है कि आप सफल हुए या नहीं, सवाल यह है कि आप सीखकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इस साल मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं और उनके परिणामों ने हज़ारों छात्रों के जीवन में नए मोड़ लाए हैं। ये परिणाम सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा भी हैं। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है। यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहाँ नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे।

हर चुनौती में छिपा होता है एक और अवसर

दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षा के रूप में लाखों छात्रों को एक और मौका दिया, यह साबित करते हुए कि एक असफलता कभी भी अंत नहीं होती। 17 जून से 5 जुलाई 2025 तक हुई इन परीक्षाओं के माध्यम से कई छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और अब वे इसे पास करने के बाद गर्व के साथ कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। यह उनकी दृढ़ता और इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है।

JEE (Mains & Advanced) और NEET जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में सफल हुए छात्र काउंसलिंग के ज़रिए प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। यदि आप पीछे रह गए हैं, तो निराश न हों! यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। एक परीक्षा में पिछड़ना आपके सपने को खत्म नहीं करता, बल्कि यह उसे और मजबूत करता है। यह आपको सिखाता है कि आपको कहाँ और कैसे सुधार करना है। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहाँ नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे। आप इससे सीखकर और भी मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यह दुनिया आगे बढ़ेगी, और आप भी, नए अवसरों और बेहतर तैयारियों के साथ!

अब क्या करें- अपनी सीख को दिशा बनाएं

- आप काउंसलिंग प्रक्रिया में सतर्क रहें, समय पर सही विकल्प चुनें।
- कॉलेज का चुनाव करते समय सिर्फ रैंक या नाम न देखें, अपनी रुचि और संस्थान की विशेषज्ञता को प्राथमिकता दें।
- उच्च शिक्षा का यह नया अध्याय आपकी खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। आप इसे मजबूती से उठाएं।
- यदि परिणाम अपेक्षित नहीं रहा: यह हार नहीं, सीखने का मौका है!
- आप अन्य विकल्पों (डिप्लोमा, स्किल कोर्स, फॉर्म भरने के नए मौके, निजी संस्थान आदि) को तलाशें।
- अगली परीक्षा की तैयारी ठोस प्लानिंग से करें, पिछली गलती दोहराएं नहीं।
- और सबसे जरूरी- खुद पर विश्वास बनाए रखें।
- प्रवेश प्रक्रिया में यह बातें ध्यान रखें:

जरूरी दस्तावेज (आधार, अंकसूची, फोटोज आदि) एक जगह व्यवस्थित रखें।

- काउंसलिंग और एडमिशन की अंतिम तिथियाँ नोट करें।
- मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों या काउंसलरों से बातचीत करें।
- कोर्स फीस और अन्य खर्चों के लिए बजट प्लानिंग करें।

ज़िंदगी में हर परिणाम एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं

जीवन की सफलता सिर्फ परीक्षा पास करने में नहीं, असफलता से दोबारा उठ खड़े होने में है। जो छात्र आज कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, उन्हें सजग, जिम्मेदार और केंद्रित रहना चाहिए। और जो अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि हर सपना समय मांगता है- हार नहीं और जो समय देता है, वही जीत के योग्य बनता है।

जनता की सुरक्षा सर्वोच्च: पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जनपदों से अतिवृष्टि, मानसून की स्थिति, चारधाम यात्रा, डेंगू की रोकथाम तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा प्रत्येक स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान प्रत्येक अधिकारी को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड में रहना होगा। किसी भी प्रकार की आपदा अथवा आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय एवं राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराई जाए तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जिलेवार सड़कों की स्थिति, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, चारधाम यात्रा मार्गों, यात्रियों की संख्या तथा विभिन्न धामों में व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी है। इसलिए यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवाजाही, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता तथा यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

R.O. No. : 13867/1

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)